Regarding the issue of vote bank politics

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, आज मैं इस देश के सामने बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं ।

सर, यह संविधान है । जो विपक्ष है, वह लगातार संविधान बचाने की बात कर रहा है । संविधान के आर्टिकल 14,15 और 16 कहता है कि धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा ।

सभापति महोदय, जब कंस्टीटूएन्ट असेम्बली बन रहा था, तब तज़ीमुल हसन साहब मुस्लिम लीग के एक एमपी थे । वह एक संशोधन लेकर आए कि मुसलमानों के लिए अलग लोक सभा और विधान सभा होनी चाहिए तथा उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए । सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्टिकल 6 के माध्यम से उसको गिराया और कहा कि पूरे भारत के जो नागरिक हैं, वे एक हैं । संविधान में जो आर्टिकल 14, 15 और 16 है, उसमें धर्म के आधार पर किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है । उसके बाद कांग्रेस का हाथ, मुसलमानों के साथ और मुसलमान की राजनीति के साथ हुआ । ? (व्यवधान) आर्टिकल 370 के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया । जब तक हमने आर्टिकल 370 खत्म नहीं किया, तक तक जम्मू-कश्मीर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला ।

सर, आज जो स्थिति है, वर्ष 2004 में एक अलग स्थिति पैदा की गई । आंध्र प्रदेश में पहली बार मुसलमान के नाम पर कांग्रेस ने चार प्रतिशत आरक्षण दिया । सुप्रीम कोर्ट ने उसको एबॉलिश किया । आज उसी को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना में, उसी को बढ़ाते हुए कर्नाटक में मुसलमान को अलग से रिजर्वेशन देने की बात हो रही है ।

सर, वर्ष 2011 में यूपीए की सरकार ने, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार यूनिवर्सिटी चलाती हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, चाहे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के रिजर्वेशन को नौकरी और एडमिशन में पूरा का पूरा खत्म कर दिया । वर्ष 2012 में जब यूपी में चुनाव हो रहा था तो एक नोटिफिकेशन जारी करके तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 4.5 परसेंट ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया । यह वही कांग्रेस है, जिसने मंडल कमीशन का विरोध किया । यह वही कांग्रेस है, जिसने वर्ष 2018 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का विरोध किया ।

आज शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी को अलग से जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, जिसे काटकर मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं, ओबीसी को देने की बात कर रहे हैं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी डिमांड क्या है?

? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जिन राज्य सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति, जिन केन्द्र सरकार के लोगों ने वोट बैंक की राजनीति में इस संविधान की ? * की है । ? (व्यवधान) राहुल गांधी जी की

पार्टी ने ऑर्टिकल-14, 15 और 16 की ?* की है। ? (व्यवधान) इन सभी को जेल भेजना चाहिए।? (व्यवधान) एक कमेटी बनानी चाहिए और इनके रिजर्वेशन को बचाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. ईशा खान चौधरी।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I will check the records. Whatever will be the fact, only that fact will go in record, not other things.